

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

	(मौजूदा बाजार मूल्य पर)			
	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. राजस्व घाटा	3.4	3.4	2.7	2.1
2. राजकोषीय घाटा	5.1	4.6	4.1	3.5
3. सकल कर राजस्व	10.0	10.4	10.8	11.3
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	45.3	44.2	43.1	41.5

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2004-05 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमान के लिए अचल विनिमय दरें अवास्तविक हैं। देनदारियों में एनएसएसएफ तथा एमएसएस देनदारियां, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल हैं।
3. तेरहवें वित्त आयोग की कार्ययोजना से तुलना अनुबंध-1 में दर्शाई गई है।

1. चालू वित्त वर्ष के दौरान चुनिंदा राजकोष संकेतकों तथा अनुवर्ती वित्त वर्षों के लिए चलायमान लक्ष्यों पर निष्पादन बजट 2010-11 में की गई वचनबद्धताओं में सुधार को दर्शाता है।

2. चालू वित्त वर्ष के प्रथमार्द्ध के दौरान, 3जी तथा बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी से अर्जित उच्च आय के साथ यह देखा गया था कि सरकार की प्राप्ति ब.अ. 2010-11 में यथा अनुमानित स्तरों से कहीं अधिक होगी। इसी दौरान कर संग्रहण में भी अनुमान से कहीं ज्यादा उछाल के संकेत मिले थे। फलस्वरूप कर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दरें भी उच्च रहीं। सरकार के समक्ष इन लक्ष्यों के दो ही विकल्प थे - पहला राजकोषीय घाटे में सुधार के मार्ग पर ज्यादा कार्य किया जाए और दूसरा रास्ता यह था कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए उच्चतर परिव्यय मुहैया कराने की दृष्टि से अतिरिक्त संसाधनों को काम में लाया जाए, परन्तु अधिदेशित घाटे के दायरे में ही रहा जाए।

3. भारत जैसे विकासशील देश में, वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना में और अधिक निवेश की जरूरत असीम है। तथापि, इसके लिए बजट में प्रावधान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इस संदर्भ में कि ब.अ. 2010-11 में व्यय के लिए आवंटन स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पार किए बिना ही किए गए थे। वर्ष के दौरान उच्चतर संसाधनों की उपलब्धता (विशेषकर 3जी तथा बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामियों से) होते ही सरकार ने दूसरे विकल्प को चुना और कतिपय क्षेत्रों,

जिनमें ग्रामीण अवसंरचना (पीएमजीएसवाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए; शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना, 4,000 करोड़ रुपए, राज्यों को योजनागत सहायता (6,379 करोड़ रुपए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण (3,657 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, समग्र व्ययों में महत्वपूर्ण इजाफे के बावजूद सरकार ने राजकोषीय समेकन को अपनी वचनबद्ध राह को छोड़ा नहीं है। स.घ.उ. में उच्चतर वास्तविक वृद्धि के साथ-साथ उच्चतर राजस्व प्राप्ति ने स.अ. 2010-11 में स.घ.उ. के 5.1 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा कम करने में सरकार की मदद की है।

4. राजकोषीय घाटे में कमी को तेल तथा उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के एवज में सरकारी प्रतिभूतियां जारी न करने के संबंध में चालू वित्त वर्ष में प्रारम्भ किए गए सरकार के नीतिगत बदलाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। स्मरणीय है कि संकट वर्ष 2008-09 में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्रभावी राजकोषीय घाटा (तेल तथा उर्वरक कंपनियों को देय सब्सिडी के एवज में जारी प्रतिभूतियों सहित) 7.8 प्रतिशत तक जा पहुंचा था। इसी के अनुरूप राजस्व घाटा जो वर्ष 2008-09 में स.घ.उ. का 6.3 प्रतिशत था, स.अ. 2010-11 में घटकर 3.4 प्रतिशत तक सीमित हो गया। चालू वित्त वर्ष से नया राजकोषीय संकेतक, नामशः प्रभावी राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। (जिसका ब्यौरा राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण में स्पष्ट किया गया है)। यह संकेतक बताता है कि पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के

राजस्व लेखों में कितना असंतुलन है। स.अ. 2010-11 में प्रभावी राजस्व घाटा स.घ.उ. का 2.3 प्रतिशत अनुमानित है।

5. ब.अ. 2010-11 में सकल कर राजस्व प्राप्तियों के वर्ष 2009-10 के वास्तविक आंकड़ों से 19.6 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान था, अब सं.अ. 2010-11 में इसका अनुमान 26 प्रतिशत किया गया है। तथापि, वर्ष 2009-10 के लिए स.घ.उ. के वृद्धिमान संशोधन तथा वर्ष 2010-11 के दौरान स.घ.उ. में यथा अनुमानित वास्तविक वृद्धि से ज्यादा रहने के साथ स.घ.उ. अनुपात के लिए कर में ब.अ. 2010-11 में 10.8 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से पूर्व सघउ संख्या के अनुसार सं.अ. 2010-11 में 10.0 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। 2004-05 से लागू स.अ.उ. आंकड़े की संशोधित श्रृंखला में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व जो कि 2007-08 में 11.9 प्रतिशत की ऊंचाई पर था, धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2009-10 में 9.5 प्रतिशत तक आ पहुंचा। स.घ.उ. अनुपात से कर में यह कमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक संकटों का प्रतिकूल प्रभावों का नतीजा था तथा इससे जुड़े राजकोषीय उपाय (करों तथा शुल्कों में कमी) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की अवधि के दौरान शुरु किए गए थे। 2010-11 के दौरान प्रेरक उपायों की आंशिक वापसी के साथ कर सम्बद्ध स.घ.उ. अनुपात में वर्ष 2009-10 में 9.5 प्रतिशत से स.अ. 2010-11 में 10.0 प्रतिशत तक हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि समुत्थानिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित बनी है और आने वाले वर्षों में मध्यावधि रूप से अगले त्वरित सुधारों के लिए कोई भी सहज अंदाज लगा सकता है।

6. कर-भिन्न राजस्व 1,48,117 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों को पार कर स.अ. 2010-11 में 2,20,148 करोड़ रुपए हो गया। ऐसा मुख्य रूप से 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी के कारण अनुमान से कहीं ज्यादा प्राप्तियों के कारण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक से यथानुमानित अधिशेषों से कम अन्तरण होने और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं से अर्जित लाभांश प्राप्तियां ब.अ. 2010-11 में किए गए अनुमान से स.अ. 2010-11 में बढ़ गईं।

7. ब.अ. 2010-11 में विनिवेश प्राप्तियों, जो गैर ऋण पूँजी प्राप्ति का महत्वपूर्ण भाग है, के 40,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि राजस्व के अन्य स्रोतों में हुई बढोतरी को ध्यान रखते हुए 2010-11 के दौरान विनिवेश कार्यक्रम में संशोधन किया गया है और तदनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से होने वाली प्राप्तियाँ स.अ. 2010-11 में घटकर 22,144 करोड़ रुपए हो गईं। ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए कुल गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों के ब.अ. 2010-11 के 45,129 करोड़ रुपए से घटकर स.अ. 2010-11 में 31,745 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

8. घाटा संबंधी अन्य वित्तपोषण स्रोतों के उच्च प्राप्तियों की वजह से सरकार का समग्र निवल बाजार उधार सं.अ. 2010-11

में घटकर 10,000 करोड़ रुपए हो गया है जबकि ब.अ. 2010-11 में यह 3,45,010 के अनुमानित स्तर पर था। उधार के इस दर्शाए गए स्तर से आगामी वर्ष की पहली तिमाही में जब मौजूदा ऋण स्टॉक का मोचन उच्च स्तर पर होगा, तो बेहतर नकद प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।

वर्ष 2011-12 और 2013-14 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

9. दो कठिन वित्त वर्षों के विराम के पश्चात् आरम्भ की गई राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जो 2010-11 में बहाल हुई, को जारी रखते हुए 2011-12 की राजकोषीय नीति बजट 2010-11 के साथ प्रस्तुत मध्यवधि राजकोषीय नीति विवरण में सरकार द्वारा की गई बचनबद्धता के साथ जारी रखी जाएगी। 13वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों की तर्ज पर राजकोषीय घाटा जिसे स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत तक कम करने की वचनबद्धता थी, के संबंध में वास्तविक रूप से सुधार होकर इसके ब.अ. 2011-12 में 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इससे आने वाले वर्षों में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखने की सरकार की वचनबद्धता को पुनः बल मिलता है। 2012-13 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत और 2013-14 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि 2012-13 का लक्ष्य 13वें वित्त आयोग (4.2 प्रतिशत) द्वारा सिफारिश की गई रूपरेखा के मुकाबले मामूली सुधार की स्थिति में है, अतः 2013-14 का लक्ष्य 3.0 प्रतिशत के मुकाबले कम महत्वाकांक्षी है। यह मुख्यतया 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुकाबले अनुमानित कम विनिवेश प्राप्तियों के कारण हुआ है, जबकि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों में 2013-14 के लिए गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में स.घ.उ. का 0.9 होने का अनुमान किया गया है और दूसरी ओर इस विवरण में स.घ.उ. का 0.3 प्रतिशत अनुमान किया गया है। 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि अर्थात् 2010-11 और 2011-12 के पहले दो वर्षों में सरकार ने राजकोषीय घाटे के सिफारिश किए गए स्तर में और अधिक सुधार करने का प्रयास किया है। जैसाकि 13वें वित्त आयोग के सुझाए गए रोडमैप में 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः स.घ.उ. का 5.1 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा होने का अनुमान किया गया था, अब क्रमशः 5.7 और 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। राजकोषीय घाटे में सिफारिश से बेहतर निष्पादन और स.घ.उ. में वृद्धि से सरकार को स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण को तीव्रता से घटाने में और 13वें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य से पहले सफलता मिलने में सहायता मिलेगी।

10. अन्तिम वर्ष (2014-15) में सिफारिश किए गए स.घ.उ. के 44.8 प्रतिशत का ऋण लक्ष्य वर्ष 2011-12 में ही प्राप्त हो जाने का अनुमान है जबकि इस वर्ष में इसका स.घ.उ. के 44.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के उपर्युक्त अनुमानों के साथ और यह मानने पर कि देयता में निवल अनुवृद्धि संबंधित वर्षों के राजकोषीय घाटे से अधिक नहीं होगी, 2012-13 और 2013-14 में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण के घटकर

क्रमशः 43.1 प्रतिशत और 41.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। चालू विनिमय दरों पर विदेशी लोक ऋण सहित ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया देयताओं में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की देयताएँ शामिल नहीं हैं जिनका उपयोग केन्द्र सरकार के घाटे के वित्त पोषण हेतु नहीं किया जाता है। इसमें 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों संबंधी देयताएँ भी शामिल हैं जिन्हें सामान्य सरकारी ऋण और देयताओं का समेकन करते समय राज्यों को केन्द्र सरकार का ऋण प्रदान करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

11. ब.अ. 2011-12 में स.घ.उ. का 3.4 प्रतिशत राजस्व घाटा होने का अनुमान है। यह स.अ. 2010-11 में यथा अनुमानित स्तर के बराबर है। तथापि, स.अ. 2010-11 की तुलना में राजस्व घाटे में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कमी न होने की वजह 2010-11 में 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए राजस्व प्राप्तियों में हुआ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। इस संघटक से हुआ योगदान जो 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे के सुधार में प्राप्त से इतर रहा, स.घ.उ. का 1.3 प्रतिशत था। राजस्व घाटे के और घटकर 2012-13 में स.घ.उ. का 2.7 प्रतिशत और 2013-14 में 2.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। जैसाकि राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण भाग के रूप में पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है, सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे को देखा जाना प्रासंगिक होगा। राजस्व खाते में ऊपर उल्लिखित अनुदान संघटक को ध्यान में रखने के बाद ब.अ.2011-12 में स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत राजस्व घाटा होने का अनुमान है। 2012-13 में इसके और घटकर 1.1 प्रतिशत और 2013-14 में 0.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजस्व खाते में असंतुलन के इस संघटक पर व्यय प्रबंधन और राजस्व संवर्धन के जरिए पूरी गंभीरता से समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

12. सकल कर राजस्व में स.अ. 2010-11 के स.घ.उ. के 10.00 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 10.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। (स.अ. 2010-11 के मुकाबले 18.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है) जो हालांकि 2007-08 में प्राप्त स.घ.उ. के 11.9 प्रतिशत की तुलना में कम है। अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर की प्रवृत्ति के मार्ग में वापस लौटने से स.घ.उ. में कर के अनुपात के प्राप्त स्तर पर वापस आना संभव होगा। मध्यावधि लक्ष्यों में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर संग्रहण 2012-13 में 10.8 प्रतिशत और 2013-14 में 11.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

13. इस विवरण में बताया गया राजकोषीय समेकन का रोडमैप सरकार के कुल व्यय को कम करके इसे स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में संकट पूर्व अवधि अर्थात् 2007-08 के स्तर के प्रतिशतांक तक लाने के एक सजग प्रयास से तैयार किया गया है। सब्सिडियों के बदले प्रतिभूतियों के निर्गम और राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों को मिलाकर 2007-08 के दौरान सरकार का कुल व्यय स.घ.उ. का 15.9 प्रतिशत था।

यह बढ़कर 2008-09 में 17.3 प्रतिशत हो गया (सब्सिडियों के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों सहित) तथा कम होकर सं.अ. 2010-11 में 15.4 प्रतिशत रह गया। व्यय को विकास कार्य में फिर से लगाने तथा गैर-विकासात्मक व्यय की वृद्धि में कमी करने के चलते कुल व्यय कम होकर ब.अ. 2011-12 में स.घ.उ. के 14 प्रतिशत तक आ जाने का अनुमान है। मध्यावधि अनुमान में यह आगे और कम होकर 2012-13 में स.घ.उ. का 13.5 प्रतिशत और 2013-14 में 13.0 प्रतिशत होने का अनुमान है।

ख. राजकोषीय संकेतकों के संबंध में पूर्वानुमान

1 राजस्व प्राप्ति

(क) कर-राजस्व

14. 2004-05 से 2007-08 की अवधि के दौरान सकल कर राजस्व स.घ.उ. के 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, वैश्विक आर्थिक संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े उसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण यह प्रतिशतांक गिरकर 2009-10 में 9.5 प्रतिशत रह गया है। अर्थव्यवस्था फिर से विकास पथ पर अग्रसर होने के चलते, सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि कर संग्रहणों को संकट-पूर्व वर्ष के स्तर पर लाया जाए। सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी होकर यह 2010-11 में स.घ.उ. के 10 प्रतिशत के स्तर से ब.अ. 2011-12 में 10.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। यह प्रतिशतांक 2008-09 के संकट कालीन वर्ष में 10.8 प्रतिशत के कर सम्बद्ध स.घ.उ. अनुपात से अभी भी कम है। 2011-12 में प्रत्यक्ष कर अधिनियम के प्रारम्भ से और वस्तु तथा सेवा कर की संभावित शुरुआत के चलते प्रयास यह है कि संकट की अवधि के दौरान कर सम्बद्ध स.घ.उ. के अनुपात में कमी लाई जाए। मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में, यह ब.अ. 2011-12 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 10.8 प्रतिशत तथा आगे और बढ़कर 2013-14 में 11.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। हालांकि यह 2007-08 के दौरान हासिल किए गए 11.9 प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है। इनमें 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए अर्थव्यवस्था में अनुमानित उच्च वृद्धि के साथ-साथ सुधार होते जाने का अनुमान है। विकास के पूर्वानुमानों में हुई किसी भी तरह की घट-बढ़ का इन अनुमानों पर असर पड़ेगा।

15. प्रत्यक्ष कर संग्रहण जो 2007-08 में स.घ.उ. के 6.3 प्रतिशत के शिखर पर पहुँच गए थे, उनके सं.अ. 2010-11 में स.घ.उ. के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 5.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। इसके सं.अ. 2010-11 की अपेक्षा ब.अ. 2011-12 में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। यह अनुमानित वृद्धि दर 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के रुख के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण के निष्पादन के अनुरूप है। ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर के प्रमुख घटकों की संयोजित वार्षिक वृद्धि लगभग 29 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था के शीघ्र और व्यापक पुनरुत्थान के प्रदर्शन और मध्यावधिक संदर्भ में विकास की उच्च दर जारी रहने की संभावना के चलते प्रत्यक्ष कर

संग्रहण संकटपूर्व वर्ष के स्तर तक पहुँच जाने चाहिए। 2012-13 से प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमित हो जाने से स.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में प्रत्यक्ष कर ब.अ. 2011-12 में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 6.2 प्रतिशत होने तथा आगे और बढ़कर 2013-14 में 6.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। उपर्युक्त पूर्वानुमानों के लिए मानी गई वर्षानुवर्ष वृद्धि दर 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 19.5 प्रतिशत और 19 प्रतिशत है। यह स्मरणीय है कि 2010-11 के दौरान डीटीसी की शुरुआत से पहले मौजूदा कर दर संरचना के लिए आय के स्लैबों में वृद्धि की गई थी तथा निगम कर पर लगने वाली अधिभार की दर घटा दी गई है। इससे कर के व्यापक आधार और अनुपालन का स्तर में सुधार हुआ। चालू वर्ष इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अधिभारों में कटौती करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निगम कर पर लगने वाली अधिभार की दर 2011-12 के दौरान और कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

16. भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक आर्थिक संकट के समय अपनी विशिष्ट समुत्थानशीलता का परिचय दिया है। यह पुनरुत्थान व्यापक हुआ है तथा इसका प्रमाण चालू वर्ष में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में हुई वृद्धि है। प्रोत्साहन उपायों को आंशिक तौर पर वापस लेने के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् ब.अ. 2010-11 में 27.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था। 2010-11 के नवीनतम रुझान दर्शाते हैं कि अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की वृद्धि बहुत अधिक होगी तथा सं.अ. 2010-11 में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में इस शीघ्र पुनरुत्थान के चलते स.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 2009-10 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर सं.अ. 2010-11 में 4.3 प्रतिशत हो जाएंगी। जीएसटी के क्रियान्वयन से अनुपालन में और अधिक सुधार लाने में मदद मिलेगी जिसका परिणाम समग्र तौर पर अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में सुधार होने में होगा। यह मानकर कि अर्थव्यवस्था उच्च विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर रहेगी, यह अनुमान है कि स.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 4.5 प्रतिशत और 2013-14 में 4.7 प्रतिशत हो जाएंगी।

17. 13वें वित्त आयोग की रिफारिशों को हिसाब में लेने के पश्चात् ब.अ. 2011-12 में राज्यों को आवंटन और केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 2,63,458 करोड़ रुपए और 6,64,457 करोड़ रुपए आंका गया है। अधिभारों में क्रमिक कटौती के चलते सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में हिस्सेदारी की राशि ब.अ. 2010-11 की तुलना में ब.अ. 2011-12 में बढ़ी है। इसलिए केन्द्र के निवल कर राजस्व का ब.अ. 2010-11 से 71.5 प्रतिशत से घटकर ब.अ. 2011-12 में 71.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

18. सारणी में पैराग्राफ क में दर्शित ब.अ. 2010-11 के राजकोषीय संकेतक नए बजट प्रस्तावों पर आधारित हैं।

(ख) कर भिन्न राजस्व

19. कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) जो ब.अ. 2010-11 में 1,48,118 करोड़ रुपए अनुमानित थे, उनमें 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी से हुई उच्च प्राप्तियों के कारण भारी बढ़ोतरी हुई। इनके सं.अ. 2010-11 में 2,20,148 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस एकबारगी प्राप्ति ने सरकार को अधिदेशित स्तर के भीतर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद दी। तथापि, 2011-12 में ऐसी किसी प्राप्ति के अभाव में कर भिन्न राजस्व के अनुमान पुनः वापसी के स्तर पर आ जाएंगे। इनके 1,25,435 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्राप्ति का अधिकांश भाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त लाभांश और लाभ सहित भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष अन्तरण की वजह से अनुमानित है। चूंकि राजस्व का यह संघटक अत्यधिक अस्थिर स्वरूप का है, इसलिए सरकार को कर भिन्न राजस्व से होने वाली प्राप्तियों को बढ़ाने की व्यवस्था खोजनी होगी। एक मद प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी मूल्य निर्धारण का हो सकता है, जो सरकार के लिए नियमित राजस्व प्रवाह का माध्यम बन सकता है। मौजूदा नीति से, अनुमान है कि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कर-भिन्न राजस्व ब.अ. 2011-12 में 1.4 प्रतिशत से घटकर 2012-13 और 2013-14 में 1.2 प्रतिशत हो जाएगा। समग्र रूप में, इसके 2012-13 में बढ़कर 10 प्रतिशत तथा 2013-14 में 7 प्रतिशत होने का अनुमान है। कहीं उछाल हो सकता है जबकि कुछ इतर मदों से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है।

(ग) राज्यों को सुपुर्दगी

20. 13वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों के हिस्से को 30.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2010-2015 की पंचाट अवधि के दौरान 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। आयोग ने केन्द्र से राज्यों को राजस्व खाते में कुल अन्तरणों से सम्बद्ध निर्देशक अधिकतम सीमा को बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। इससे केन्द्र सरकार के संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हुई।

2. पूंजी प्राप्तियां

(क) ऋण तथा अग्रिमों की वसूली

21. राज्यों से ऋणों की निवल वसूली 12वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा क्रमिक अमध्यस्थीकरण और ऋण समेकन तथा ऋण माफी योजना के कारण घटी। तथापि, 12वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के व्यतित होने पर ऋण माफी योजना आगे प्रभाव में नहीं रहेगी और इसलिए राज्यों से ऋणों की वसूली में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गयी।

22. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) से ऋणों की पुनःअदायगी भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर बकाया राशि होने से प्रभावित हुई। ये उद्यम या तो रुग्ण हैं अथवा बीआईएफआर के जरिए पुनरुद्धार के अधीन हैं। रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ब्याज माफी अथवा ऋणों को बट्टे खाते डालने से भावी

प्राप्तियों की सम्भावना भी घटी। ब.अ. 2011-12 में ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली 15,020 करोड़ रुपए अनुमानित है। उच्च अनुमानित प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम को अपने अधिप्राप्ति कार्यकलाप के लिए दिए गए अत्यावधि ऋण की वसूली के कारण हैं। 2011-12 और 2013-14 के सम्बन्ध में प्राप्ति के इस संघटक का एक समान 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चूंकि सरकार निवल ऋण प्रदान करने को प्रोत्साहित नहीं करेगी (राज्यों को विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में की गयी दुतरफा व्यवस्था के सिवाय)।

(ख) अन्य ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां

23. इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्राप्तियों का एक मुख्य स्रोत है। राष्ट्रीय निवेश निधि का सृजन निधि के अन्तर्गत फंड मैनेजर्स द्वारा विनिवेश प्राप्तियों और निवेश संचय को धारित करने हेतु किया गया है जिसका उपयोग 2008-09 तक सरकार के कर-भिन्न राजस्व के रूप में प्रतिलाभ देने के लिए किया जाता है। 2009-10 के दौरान, सरकार ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग ऐसे सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ किया था जो पूंजी परिसम्पत्तियों का सृजन कर रहे हैं। तदनुसार, विनिवेश प्राप्तियों का आंशिक उपयोग ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवासन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, शहरी अवसंरचना तथा विद्युत क्षेत्र में सुधार जैसे चुनिंदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों में किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में सरकार ने विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। कोल इंडिया से सम्बद्ध सबसे बड़े आईपीओ के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर इस लक्ष्य को मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। तथापि, सरकार के राजस्व के अन्य स्रोत से प्राप्तियों में अद्यतन प्रवृत्तियों की समीक्षा करने पर, 2010-11 के दौरान विनिवेश कार्यक्रम में शिथिलता बरती गयी और सं.अ.2010-11 में ये प्राप्तियां 22,144 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ब.अ. 2011-12 में इनके 40,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। साथ ही, राष्ट्रीय निवेश निधि के जरिए निवेशों से अर्जित प्रतिलाभों को ऐसे चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के वित्तपोषण हेतु नियोजित किया जाता रहेगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को प्रोत्साहन देती हैं और लाभ तथा पुनरुद्धार योग्य केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश आवश्यकता की पूर्ति करती है।

24. 2012-13 के दौरान, सरकार के मौजूदा निर्णय के अनुसार, विनिवेश प्राप्तियां कार्यक्रम व्यय के वित्त पोषण हेतु उपलब्ध नहीं होंगी तथा पूर्व के प्रतिलाभ और भावी निवेशों को केवल चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा। तथापि, 13वें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत, इस विवरण के मध्यावधि दृष्टिकोण में यह अनुमान लगाया गया कि विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग 2012-13 तथा 2013-14 में भी सरकारी व्यय के वित्त पोषण में किया जाता रहेगा। इस संघटक के अन्तर्गत प्राप्तियां

2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः 30,000 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए होंगी। यह सम्बद्ध वर्षों हेतु स.घ.उ. का 0.3 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत है जो 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित प्राप्तियों से काफी कम हैं। यह प्राप्ति सरकार को राजकोषीय घाटे को मध्यावधि फ्रेमवर्क में निर्देशित स्तर पर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायक होगी। तथापि, कार्यक्रम व्यय के वित्त पोषण हेतु विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग को समाप्त करने से 2012-13 और 2013-14 में राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक होगा। अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार दशा और मौजूदा वृहद् आर्थिक मानदंडों को देखते हुए, उच्च तथा निम्न दोनों जोखिम सम्बद्ध वर्षों में विनिवेश कार्यक्रम के अनुमानित स्तर के सफलतापूर्वक पूर्ण करने से जुड़े हैं।

(ग) उधार - लोक ऋण और अन्य देनदारियां

25. बजट 2010-11 में, यह घोषणा की गयी थी कि सरकार एक अध्ययन पत्र लाएगी जिसमें सरकार की ऋण स्थिति का ब्यौरेवार विश्लेषण तथा समग्र लोक ऋण में कटौती का एक रोडमैप दिया होगा। यह भी घोषणा की गयी थी कि इसके बाद इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी आएगी। उपर्युक्त घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नवम्बर, 2010 में "सरकारी ऋण-प्रास्थिति तथा आगामी कार्रवाई" नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। केन्द्र सरकार की ऋण तथा देयताओं के समग्र अध्ययन से लगभग 92 प्रतिशत घरेलू ऋण और केवल 8 प्रतिशत विदेशी ऋण हैं। वर्तमान में, सरकार के घाटे का वित्त पोषण मुख्यतः बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर दिनांकित प्रतिभूतियों से जो नीलामी से जुटाई जाती है, किया जाता है। सरकार के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियां, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त विदेशी ऋण, अत्यावधि बिल, सरकार के लोक लेखे में निवल उपचय शामिल हैं।

26. 2010-11 के दौरान, बाजार उधार कार्यक्रम बजट अनुमानों में अनुमानित स्तर से घटकर 10,000 करोड़ रुपए हो गया। घोषित उधार कलेंडर लगभग पूरा हो गया है और घोषित कलेंडर से शेष 10,000 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाने का निर्णय सरकार की नकद स्थिति को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा। मौद्रिक नीति में परिवर्तन और मौजूदा नकदी दशा के फलस्वरूप मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान आय में वृद्धि हुई। 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियों की प्रारंभिक नीलामी में भारांश औसत आय 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। 2011-12 में सरकार बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए लगभग 82 प्रतिशत घाटे का वित्त पोषण करेगी। 2011-12 में खुले बाजार से निवल उधारों का अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद लगाया गया है। ये ब.अ. 2010-11 में स.घ.उ. के 5.0 प्रतिशत से घटकर ब.अ. 2011-12 में 3.8 प्रतिशत अनुमानित हैं। बैंकिंग प्रणाली में समग्र जमाराशियों के अनुपात के रूप में भी, अनुमानित बाजार उधारों में ब.अ. 2010-11 की तुलना में ब.अ.

2011-12 में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई देगी। घाटे के वित्त पोषण के अन्य स्रोतों के विवरण प्राप्ति बजट में दर्शाए गए हैं।

27. ऋण दस्तावेज (नवम्बर, 2010)में, यह स्पष्ट किया गया था कि केन्द्र सरकार के ऋण और देनदारियों का परिकलन करते समय, केन्द्र सरकार के घाटे के वित्त पोषण के लिए प्रयोग न की गई राशि को सरकार की देनदारी का वास्तविक चित्रण करने हेतु निकाल लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय लघु बचत निधि के घटकों को जिन्हें राज्य सरकार की प्रतिभुतियों के रूप में निवेश किया जाता है, को केन्द्र सरकार की देनदारियों के परिकलन के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं किया गया है। बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अधीन जुटाया गए ऋण जो सरकार के घाटे के वित्त पोषण के अनुपलब्ध समतुल्य परिबद्ध नकदी से समर्थित हैं, को भी केन्द्र सरकार की ऋण और देनदारियों को तय करते समय समायोजित किया जाता है। वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण सहित प्राप्ति बजट अनुबन्ध-5क में दर्शाई गई देनदारियों से इन समायोजनों से, केन्द्र सरकार का स.घ.उ. से अनुमानित ऋण का अनुपात क्रमशः सं.अ. 2010-11 में 45.3 प्रतिशत और ब.अ. 2011-12 में 44.2 प्रतिशत होगा। ऋण के संबंध में पहले सूचित आंकड़ों से इस उल्लेखनीय सुधार को 2004-05 से प्रभावी नई श्रृंखला तथा 2009-10 तथा 2010-11 में पहले अनुमानित वृद्धि की अपेक्षा उच्चतर वृद्धि के चलते स.घ.उ. आंकड़ों में संशोधन के संदर्भ में देखा जाना होगा। 2012-13 में स.घ.उ. के 4.1 प्रतिशत और 2013-14 में स.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत के घाटे के अनुमानित स्तर के रहते स.घ.उ. से ऋण का अनुमानित अनुपात क्रमशः 43.1 प्रतिशत और 41.5 प्रतिशत होगा। ये अनुमान दर्शाते हैं कि स.घ.उ. से ऋण का अनुपात 2011-12 में ही 13वें वित्त आयोग द्वारा मियादी वर्ष 2014-15 तक 44.8 प्रतिशत के अनुशासित स्तर तक कम हो जाएगा।

3. कुल व्यय

(क) राजस्व खाता

(i) आयोजना राजस्व व्यय

28. 2008-09 से आरंभ करके और पुनः 2009-10 में, सरकार को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मांग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजना व्यय में काफी अधिक वृद्धि करना पड़ी थी। यह निर्णय सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का भाग था। यह तथ्य कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2009-10 में 8 प्रतिशत की दर पर बढ़ी थी, दर्शाता है कि सरकारी आयोजना व्यय में वृद्धि की नीति ने अर्थव्यवस्था के तीव्र और व्यापक पुनरुत्थान में सहायता की है। आयोजना राजस्व व्यय 2007-08 में 1,73,572 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2010-11 के दौरान 3,26,928 करोड़ रुपए हो गया है। यह 2008-09 से 2010-11 के दौरान 23.5 प्रतिशत की यौगिक वृद्धि दर्शाता है। आयोजना राजस्व ब.अ. 2011-12 में 3,63,603 करोड़ रुपए अनुमानित है जो सं.अ.

2010-11 की तुलना में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

29. इन आवंटनों से, आयोजना व्यय हेतु समग्र प्रावधान वास्तविक संदर्भ में ग्यारहवीं योजना में अनुमानित व्यय परिव्यय से अधिक हो जाएगा। इसे 9वीं और 10वीं योजना के दौरान पूर्ववर्ती निष्पादनों के संदर्भ में देखा जा सकता है जब वास्तविक व्यय अनुमानित परिव्यय का केवल लगभग 84 प्रतिशत था। आवंटनों में यह महत्वपूर्ण वृद्धि परिव्यय को परिणामों में तब्दील करने के मुद्दे को सामने लाती है, विशेषकर उन परिणामों को जिन्हें मध्यावधि में आधार परिदृश्य से मानीटर किया जा सकता है।

(ii) आयोजना भिन्न राजस्व व्यय

30. आयोजना भिन्न राजस्व व्यय जिसमें मुख्यतः वेतन, पेंशन, रक्षा सेवाएं, ब्याज भुगतान और राज्यों को सांविधिक अनुदान शामिल हैं, 2008-09 और 2009-10 की संकटग्रस्त अवधि के दौरान तेजी से बढ़ा है। 2006-07 में स.घ.उ. के 9.6 प्रतिशत से यह 2009-10 में बढ़कर 11.0 प्रतिशत हो गया है। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि का यह स्तर अवहनीय पाया गया है और सरकार के मौजूदा संसाधनों से इसे पूरी तरह वित्तपोषित नहीं किया जा सकेगा; अतः इस घटक को वित्तपोषित करने के लिए उधार के संसाधनों का प्रयोग आवश्यक हो जाएगा। स.घ.उ. के सापेक्ष वेतन और पेंशन से सम्बन्धित व्यय में निम्नतर वृद्धि के अनुमान तथा किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के पूरा हो जाने से, आयोजना-भिन्न राजस्व में वृद्धि कम हुई है और तदनुसार ब.अ. 2011-12 में समग्र आवंटन को स.घ.उ. के 8.2 प्रतिशत तक नीचे लाया गया है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में इस तीव्र कमी को 2010-11 के दौरान देखी गई स.घ.उ. में वास्तविक वृद्धि दर की बहुत उच्च दर के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तथापि चुनौती इन आवंटनों पर अडिग रहने और अनुदानों की पूरक मांगों के जरिए बहुत अधिक बढ़ोतरियों का सहारा न लेने की है।

31. समग्र रूप में, आयोजना-भिन्न के सं.अ. 2010-11 में 7,26,749 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 7,33,559 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 1 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की प्रमुख मदों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) ब्याज अदायगियां

32. वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान, कम ब्याज दर प्रणाली की सहायता से राजकोषीय समेकन से सरकार को केन्द्रीय सरकार के निवल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में ब्याज अदायगी कम करने में मदद मिली। यह 2004-05 में 56.5 प्रतिशत के उच्च शिखर से कम होकर 2007-2008 में 38.8 प्रतिशत पर आ गयी थी। तथापि, संकट की अवधि में उच्चतर राजकोषीय घाटे से ब्याज के रूप में अधिक राशि देनी पड़ी जिससे निवल कर राजस्व में कमी आ जाने से केन्द्र के निवल कर राजस्व के अंश के रूप में ब्याज अदायगी बढ़ कर 2009-10 में 46.7

प्रतिशत हो गयी। केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय समेकन के पथ पर लौटने से, इस प्रतिशत के सुधर कर ब.अ. 2011-12 में 40.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। इससे यह इंगित होता है कि एक या दो वित्तीय वर्षों के लिए भी राजकोषीय मार्ग पर किसी भी भटकाव से, भविष्य में, विकासात्मक व्यय के लिए संसाधनों का गंभीर संकट हो सकता है क्योंकि ब्याज अदायगी सरकार के निवल कर राजस्व से अन्य खर्चों को कम कर देगी। मध्यावधिक दृष्टिकोण से यह अनुपात 2012-13 और 2013-14 में सुधर कर क्रमशः 38.4 प्रतिशत एवं 36.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में ब्याज अदायगी का अनुमान 2009-10 में हुए 3.3 प्रतिशत से कम होकर ब.अनु. 2011-12 में 3.0 प्रतिशत और 2013-14 तक 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। उपर्युक्त अनुमानों से सम्बद्ध जोखिम यह है कि आगामी वर्षों में ब्याज दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है अथवा तदनुसारी अवधि के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा अधिक हो सकता है।

(ख) रक्षा सेवाएं

33. राजस्व खाते में रक्षा सेवा व्यय, 2009-10 में हुए 90,669 करोड़ रुपए से मामूली बढ़कर सं. अनु 2010-11 में 90,748 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस संघटक में कम वृद्धि, 2009-10 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण हुई है। इसके ब.अनु. 2011-12 में बढ़कर 95,217 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें सं. अनु 2010-11 से 4.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलाक्षित होती है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में, इस संघटक के, 2009-10 में 1.4 प्रतिशत से कम होकर, ब.अनु. 2011-12 में 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) मुख्य आर्थिक सहायता

34. ज्ञातव्य है कि खाद्य, उर्वरकों पेट्रोलियम पदार्थों पर दी गयी आर्थिक सहायता पर व्यय 2008-09 में काफी बढ़ गया है। तेल और उर्वरक कम्पनियों को नकद आर्थिक सहायता के एवज में जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियों की 95,942 करोड़ रुपए की राशि को जोड़ने के बाद, इन तीन वस्तुओं पर दी गयी आर्थिक सहायता पर कुल व्यय बढ़कर 2,19,582 करोड़ रुपए हो गया। यह राशि सरकार की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत होती है। आर्थिक सहायता भुगतान का यह स्तर निश्चित रूप से वहनीय नहीं था और सरकार ने उर्वरकों के लिए पोषक आधारित सब्सिडी प्रणाली, पेट्रोल कीमत निर्धारण से नियंत्रण हटाने की शुरुआत जैसे कतिपय उपाय किए हैं। इन उपायों का ब्योरा राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में दिया गया है। इन उपायों से मुख्य सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को कम करके ब.अनु. 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 1.5 प्रतिशत करने में मदद मिली है तथा इसके, 2013-14 तक, कम करके 1.3 प्रतिशत करना

अनुमानित है। सब्सिडियों के लिए मध्यावधिक अनुमान, निरपेक्ष रूप से, 5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का लगाया गया है। आर्थिक सहायता (सब्सिडियों) के विषय में नीति को वितरण प्रणाली में सुधारों सहित पुनः कारगर बनाना होगा ताकि उपर्युक्त अनुमान न बढ़ पाए। इस निमित्त कोई भी भटकाव भविष्य में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है।

35. सरकार ने पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी, प्रतिभूतियों के बजाय, नकद में देने की प्रथा दृढ़ता पूर्वक स्थापित की है। सरकार नकद में सरकारी सहायता देने की इस परिपाटी को जारी रखना चाहेगी। यह सभी प्रकार की सब्सिडी संबंधी देनदारियों को सरकार के राजकोषीय लेखा-हिसाब में लाने के लिए एक मुख्य कदम उठाया गया है तथा सब्सिडी व्यय में समग्र सुधार इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

36. भारतीय खाद्य निगम को बाजार संबद्ध दर पर कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ने उच्च लागत निधियों पर उनकी निर्भरता को कम करने में मदद की है। इसने बदले में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्याज लागत को कम किया है। यह प्रथा आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी। एफसीआई अपनी प्रशासनिक लागत को और तर्कसंगत बनाने की संभावना पर विचार कर सकती है। विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली में सम्मिलित होने के लिए राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है ताकि देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की समग्र लागत को कम किया जा सके।

37. इन धारणाओं कि विश्व पण्य बाजारों में 2011-12 के दौरान विद्यमान कीमत स्तर प्रचलित रह सकता है तथा सुधार उपायों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ब.अनु. 2011-12 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 49,998 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ब.अनु. 2011-12 में खाद्य सब्सिडी का अनुमान 60,573 करोड़ रुपए लगाया गया है। ब.अनु. 2011-12 में तेल विपणन कंपनियों को कम वसूलियों की क्षतिपूर्ति सहित पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 23,640 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गयी है।

38. निरपेक्ष रूप में प्रमुख सब्सिडियों का प्रावधान सं.अ 2010-11 के 1,53,962 करोड़ रुपए से घटकर ब.अ. 2011-12 में 1,34,211 करोड़ रुपए किए जाने का अनुमान है। कुल सब्सिडियों के सं.अ. 2010-11 के 1,64,153 करोड़ रुपए से ब.अ. 2011-12 में 1,43,570 करोड़ रुपए किए जाने का अनुमान है। सब्सिडी प्रावधान के वर्तमान स्तर का अनुमान इस आधार पर किया गया है कि 2011-12 की संपूर्ण अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा। साथ ही साथ यह भी अनुमान किया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत आवंटित मात्रा व्यय और अधिप्राप्ति लागत वर्ष के दौरान कुल मिलाकर स्थिर रहेगी। इन प्रावधानों के प्रभावी उपयोगों को सुनिश्चित करने और इस व्यय को नहीं होने देने के लिए और अधिक उपायों और

साधनों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है जिससे भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में वर्धित निवेश हेतु और अधिक राजकोषीय गुंजाइश उत्पन्न की जा सके।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न अनुदान

39. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में आयोजना-भिन्न अनुदान 2009-10 के 45,947 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 66,311 करोड़ रुपए हो गया। निम्नलिखित श्रेणियों के तहत अनुदानों की सिफारिश 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई है और ये अनुदान ब.अ. 2011-12 में प्रदान किए गए हैं और 2012-13 और 2013-14 के अनुमानों में इन्हें ध्यान में रखा गया है।

अंतरण-पश्च आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा (एनपीआरडी) निष्पादन प्रोत्साहन, बुनियादी शिक्षा, परिणाम सुधार, पर्यावरण संबंधी, सड़कों का रख-रखाव, राज्य-विशिष्ट, स्थानीय निकाय, आपदा राहत और माल एवं सेवा कर का कार्यान्वयन (ब.अ. 2011-12 में शामिल नहीं किया गया है परन्तु 2012-13 और 2013-14 के लिए इन्हें ध्यान में रखा गया है।)

40. 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान सिफारिश किए गए कुल अनुदान की राशि 3,18,581 करोड़ रुपए है और यह 12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों से कहीं अधिक है। साथ-ही-साथ राज्यों को केन्द्रीय करों को अधिक प्रतिशत के भाग के रूप में अंतरित किए जाने की सिफारिश केन्द्र सरकार के लिए अपने व्यय हेतु राजस्व संसाधनों में उपलब्धता कम हो जाएगी। तदनुसार 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान आने वाले वर्षों में राजस्व घाटे में कमी आ जाएगी।

41. 2010-11 में केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को राजस्व की हानि, जो केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को समाप्त किए जाने के कारण हो सकती है; की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी वचनबद्धता जारी रखी है। इस प्रयोजन के लिए सं.अ. 2010-11 में 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और ब.अ. 2011-12 में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

42. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों और संभावित अन्य आयोजन-भिन्न अनुदानों के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले कुल आयोजना-भिन्न अनुदानों के 2012-13 और 2013-14 में सघउ का 0.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। इन अनुमानों से यह भी पता चलता है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र को प्राप्त कर राजस्व (निवल) के प्रतिशत के रूप में प्राप्त होने वाला आयोजना-भिन्न अनुदान सं.अ 2010-11 के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 10 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) पेंशन

43. छठे वेतन आयोग के कार्यावयन के बाद, पेंशन पर व्यय 2007-08 में 24,261 करोड़ रुपए से बहुत अधिक बढ़कर 2009-

10 में 56,149 करोड़ रुपए हो गया है। यह वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बकाया के भुगतान के घटक के कारण भी थी। पेंशन व्यय, जो 2007-08 में केन्द्र के कर राजस्व (निवल) का 5.5 प्रतिशत और स.घ.उ. का 0.5 प्रतिशत था; सं.अ. 2009-10 में बढ़कर क्रमशः 12.3 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत हो गया है। 2009-10 में बकाया का भुगतान पूरा हो जाने से, इन प्रतिशतों के 2009-10 में कम होकर 8 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत हो जो का अनुमान है। तथापि बकाया का भुगतान पूरा हो जाने पर, ब.अ. 2011-12 में इन अनुपातों के 8.2 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

44. यह मानने पर कि पेंशन सम्बन्धित व्यय आने वाले वर्षों में 5 प्रतिशत पर बढ़ सकता है, 2013-14 तक पेंशन अदायगियां घटकर स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत रह जाएंगी और उसी वर्ष केन्द्र के निवल कर राजस्व के 6.5 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी। उपर्युक्त परिकल्पना आने वाले वर्षों में सेवा छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या के जोखिम से जुड़ी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इस मद में आने वाले वर्षों में अनुमान की अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी।

(ख) पूंजी खाता

(i) ऋण और अग्रिम

45. राज्यों के बाजार से सीधे घरेलू ऋणों की संविदा करने से, निवल ऋण और अग्रिमों में माध्यमावधि में कमी आने की संभावना है। तथापि राज्यों को विदेशी ऋण केन्द्रीय सरकार के माध्यम से दिए जाते रहेंगे।

46. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी विभिन्न प्रयोजनों हेतु आयोजना भिन्न ऋण दिए जाते हैं। इन प्रयोजनों में निवेश के लिए बजटीय सहायता, पुनर्गठन/पुनरुद्धार तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना शामिल हैं।

(ii) पूंजी परिव्यय

47. ब.अ. 2011-12 में कुल पूंजी व्यय 1,60,567 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें आयोजना पूंजी व्यय 2009-10 में 49,507 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2010-11 में 68,096 करोड़ रुपए और ब.अ. 2011-12 में 77,943 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो दो वर्ष की अवधि में 25.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्रदर्शित करता है। समग्र सरकारी प्रणाली के लिए अधिकांश पूंजी व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार के लेखा में गणना में लिए जा रहे हैं। यह सामान्य सरकारी स्तर पर किए गए पूंजी निवेश को कमतर आंकता है। वर्तमान परिदृश्य में, जब पूंजी बाजार स्थिर और मजबूत हो चुका है और जब पूंजी व्यय के रूप में अनेक क्षमता वर्धन सरकारी निजी भागीदारी पद्धति से किए जा रहे हैं, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने पूंजी व्यय का काफी बड़ा हिस्सा आन्तरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों (रेलवे सहित) का आईईबीआर

सं.अ. 2010-11 में 2,03,638.08 करोड़ रुपए से 26.2 प्रतिशत बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 2,56,935.99 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

48. आयोजना-भिन्न राजस्व में मुख्यतया रक्षा व्यय शामिल है। रक्षा पूंजीगत व्यय के सं.अ. 2010-11 में 60,883 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2011-12 में 69,199 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि समग्र आयोजना-भिन्न पूंजीगत व्यय के सं.अ. 2010-11 में 94,802 करोड़ रुपए से घटकर 82,623 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह कमी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी रूप में पूंजी लगाने जैसे कुछ पूंजीगत व्यय को आयोजना-भिन्न से आयोजना व्यय में बदलने के कारण है। इसके अतिरिक्त, ब.अ. 2011-12 में कमी भारतीय खाद्य निगम को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकता में वृद्धि करने के लिए अल्पावधिक ऋण के रूप में सं.अ. 2010-11 में 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के कारण भी है। यह वृद्धि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के पूरा होने के कारण भी है।

4. सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

49. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 2010-11 का बजट प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रीय आय के परिकलन के लिए आधार वर्ष में और संशोधन किया गया है। इस परिवर्तन से, स.घ.उ. के परम्परागत अनुमानों में 2004-05 से परिवर्तन हुआ है। आंकड़ों की संशोधित श्रृंखला दर्शाती है कि वर्ष 2009-10 के दौरान उपादान लागत पर (स्थिर 2004-2005 मूल्यों पर) वार्षिक वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 2008-09 के दौरान 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 8.0 प्रतिशत हुई है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों में 2010-11 के लिए वृद्धि दर वास्तविक रूप में 8.6 प्रतिशत और मुद्रास्फीति संभावना को गणना में लेने के बाद 2010-11 के लिए स.घ.उ. वृद्धि (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) 20.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2010-11 के लिए स.घ.उ. (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) 78,77,947 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011-12 में, यह मानने पर कि अर्थव्यवस्था चल रहे रुझान की वृद्धि दर पर बढ़ते रहेगी, वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 9.0 प्रतिशत मानी गई है। 2011-12 के दौरान 5 प्रतिशत की अनुमानित मुद्रास्फीति को हिसाब में लेने के बाद, 2011-12 के लिए स.घ.उ. वृद्धि (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) 14.0 प्रतिशत होने का अनुमान है जिसके परिणामस्वरूप स.घ.उ. 89,80,860 करोड़ रुपए (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) हो जाएगी। 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए, वास्तविक वृद्धि दर 9.0 प्रतिशत मानी गई है और मध्यमावधि मुद्रास्फीति संभावना को हिसाब में लेने के बाद, 2012-13 और 2013-14 के लिए स.घ.उ. वृद्धि वर्तमान बाजार मूल्यों पर 13.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) निम्नलिखित के संबंध में सतत मूल्यांकन

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

50. राजस्व लेखा में संतुलन को सरकार के तीन स्तरों अर्थात्

केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों के समेकित लेखा के संदर्भ में देखा जाना होगा। यह भारतीय संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है क्योंकि अंतर सरकारी अंतरण की बड़ी राशि केन्द्र से राज्यों तथा राज्यों से स्थानीय निकायों तक पहुंचती है। यदि सरकार के विभिन्न टियरों के राजकोषीय खाते को पृथक तरीके से देखें तो यह राजस्व खाते में असंतुलन के सही चित्रण को विकृत करता है। वर्तमान सूचना प्रणाली एक अंतराल के बाद केंद्र तथा राज्य स्तर पर आंकड़ों का मिलान मुहैया कराती है। तथापि, यह विश्लेषण करना गलत नहीं होगा कि सरकार के अन्य टियरों के साथ-साथ अन्य अनुदान देने वाले निकायों को पूंजी परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में किए गए अंतरणों से केन्द्र सरकार के राजस्व खाते में कितना असंतुलन बढ़ रहा है। ब.अ. 2011-12 के लिए इसकी कवायद की गई है और इसमें यह बेहतर तरीके से स्पष्ट होता है कि राजस्व खाते में प्रभावी असंतुलन कितना है जिसका सरकार द्वारा गंभीरता से समाधान किए जाने की जरूरत है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के रूप में राजस्व खाते में व्यय जो ब.अ. 2011-12 में स.घ.उ. का 1.6 प्रतिशत है, को हिसाब में लेने के बाद केंद्र सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा 3.4 प्रतिशत (तकनीकी परिभाषा के अनुसार) से कम होकर स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत तक आता है। सरकार का यह प्रयास होगा कि इस घाटे को समयबद्ध तरीके से खत्म किया जाए। 2012-13 और 2013-14 के लिए व्यय के अनुमानित स्तर के साथ-साथ यह धारणा कि उपर्युक्त अनुदान में मध्यावधि में 10 प्रतिशत से कम की वृद्धि नहीं होगी, के चलते प्रभावी राजस्व घाटा कम होकर 2013-14 में स.घ.उ. का 0.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। नीतिगत उपाय और प्रशासनिक कार्यक्षमता से 2013-14 तक प्रभावी राजस्व घाटे को खत्म करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए

बाजार उधारों समेत पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग

51. आयोजना-भिन्न व्यय 2009-10 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 126 प्रतिशत रहने के फलस्वरूप उपभोग्य व्यय के लिए उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग करना पड़ा। इससे हम फिर से व्यय की संरचना में संरचनागत समस्याओं के मुद्दे पर लौट आए हैं, जिसका समाधान न किए जाने पर विकासात्मक कार्य करने के लिए राजकोष में गुंजाइश और अधिक कम होती रहेगी। सरकार ने 2011-12 की कार्यनीति बनाते समय इन मुद्दों का गंभीरता से समाधान किया है। फोकस आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि पर अंकुश लगाने पर होने के चलते ऊपर उल्लिखित प्रतिशतांक गिरकर ब.अ. 2011-12 में 103 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। अग्रताप्राप्त क्षेत्रों को संसाधनों के आगे और पुनःआवंटन करने से यह गिरकर 2013-14 में कुल राज्य प्राप्तियों का 90 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

52. ब.अ. 2011-12 में 4,41,547 करोड़ रुपए का कुल आयोजना

व्यय अनुमानित राजकोषीय घाटे का लगभग 107 प्रतिशत है। यह 2009-10 के दौरान राजकोषीय घाटे का मात्र 72 प्रतिशत था। यह उधार लिए गए संसाधनों के अभिनियोजन में हुए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। सरकार आयोजना-भिन्न व्यय विशेषकर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण प्राप्तियों

का इस्तेमाल न किए जाने हेतु आगे प्रयास करेगी। यह प्रयास स.घ.उ. ऋण तथा केंद्र की ब्याज अदायगी और निवल कर राजस्व का अनुपात कम करने और धीरे-धीरे वहनीय स्तर पर लाने तथा उधार ली गई निधियों का विवेक सम्मत प्रयोग करने का होगा ।

13वें वित्त आयोग के राजकोषीय रोडमैप के साथ एमटीएफपी की तुलना

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटा				
एमटीएफपी	5.1	4.6	4.1	3.5
13वां वित्त आयोग	5.7	4.8	4.2	3.0
राजस्व घाटा#				
एमटीएफपी	3.4	3.4	2.7	2.1
13वां वित्त आयोग	3.2	2.3	1.2	0.0
ऋण *				
एमटीएफपी	45.3	44.2	43.1	41.5
13वां वित्त आयोग	53.9	52.5	50.5	47.5

* इसमें राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण एमएसएस के अन्तर्गत ऋण शामिल नहीं है और मौजूदा विनिमय दर पर विदेशी ऋण हेतु परिकलन के लिए है।

राजस्व घाटा लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण के उक्त पैरा 50 और भाग ग में स्पष्ट किया गया है।